Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

22 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. संसद सत्र से पहले स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।

21 जुलाई 2025 को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और चिकित्सीय सलाह का हवाला देते हुए अपने पद से मध्यावधि में ही इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले एक रिक्ति उत्पन्न हो गई है।

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने त्यागपत्र में, जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(ए) का हवाला दिया, जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर किसी भी समय पद से इस्तीफा देने की अनुमति देता है। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद अब आधिकारिक रूप से रिक्त माना जाता है, और उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा एक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा।

• 18 मई 1951 को राजस्थान के किठाना में जन्मे जगदीप धनखड़ एक वकील से राजनेता बने हैं। उन्होंने 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (2019-2022) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री (1990-1991) रह चुके हैं।

• धनखड़ ने अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की सलाह के बाद पद छोड़ दिया। इससे पहले, उन्हें हृदय संबंधी बीमारियों के कारण 9-12 मार्च 2025 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS), नई दिल्ली में डॉ. राजीव नारंग की देखरेख में क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) में भर्ती कराया गया था, और जून में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें थोड़ी देर के लिए बेहोशी भी आई थी।

Key Points:-

(i) मानसून सत्र शुरू होते ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की घोषणा पर मिली-जुली राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ हुईं। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिपरिषद और सांसदों के सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इस बीच, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस समय को "अप्रत्याशित" बताया और कहा कि "जो दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा है।"

(ii) उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देने के बाद, राज्यसभा के उपसभापति अस्थायी रूप से सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। भारत के चुनाव आयोग को इस रिक्ति को भरने के लिए शीघ्र ही उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की आवश्यकता है। अगला कार्यकाल 2027 के मध्य तक चलेगा।

(iii) अपने कार्यकाल के दौरान, धनखड़ ने संसदीय सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि उपाध्यक्ष पैनल का विस्तार, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होने से उन्हें "भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की अमूल्य अंतर्दृष्टि" प्राप्त हुई, और उन्होंने इसे एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय दौर में एक विशेषाधिकार बताया।

2. असम के मुख्यमंत्री ने दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'दूध सब्सिडी योजना' की शुरुआत की।

20 जुलाई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान दूध सब्सिडी योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राज्य में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है।

- **इस योजना के तहत, सहकारी प्रसंस्करण इकाइयों को आपूर्ति किए गए दूध पर किसानों को प्रति लीटर ₹5 की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति दिन 30 लीटर प्रति किसान तय की गई है। यह योजना असम के 601 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20,000 दुग्ध उत्पादकों को लाभ देगी।**

- **इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) में कुल ₹10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसका लक्ष्य राज्य की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।**

Key Points:-

(i) उद्घाटन समारोह में, मुख्यमंत्री ने पंजाबारी दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के विस्तार कार्य के लिए भूमि पूजन भी किया। यह संयंत्र वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (WAMUL) द्वारा पुराबी डेयरी ब्रांड के अंतर्गत संचालित किया जाता है।

(ii) संयंत्र विस्तार परियोजना की अनुमानित लागत ₹104.55 करोड़ है, जिसके अंतर्गत संयंत्र की क्षमता को 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन (LLPD) से बढ़ाकर 3 LLPD किया जाएगा।

(iii) यह पहल असम डेयरी विकास योजना (ADDP) का हिस्सा है, जिसे WAMUL और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। इस योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य असम की औपचारिक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 10 LLPD तक बढ़ाना है।

3. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 'युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन' का उद्घाटन किया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 19 जुलाई, 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में 'युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन' का उद्घाटन किया।

- **शिखर सम्मेलन का आयोजन "विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा" विषय के अंतर्गत किया गया, जिसमें भारत भर के 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक युवा प्रतिनिधि एक साथ आए।**

• यह कार्यक्रम युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (MYAS) द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MoLE) के सहयोग से युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन पर अंकुश लगाने के राष्ट्रीय आंदोलन के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन ने युवा आध्यात्मिक नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और संस्थाओं को नशे की लत के व्यवहारिक समाधानों पर विचार-विमर्श करने और आध्यात्मिक रूप से जागृत, नशामुक्त भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया।

• केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए, जिनमें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (MSJE), डॉ. वीरेंद्र कुमार, गृह एवं संस्कृति राज्य मंत्री, नित्यानंद राय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (MoS), गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल थे। इन नेताओं ने सक्रिय सामुदायिक और आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए युवा प्रतिभागियों के साथ सत्रों में भाग लिया।

Key Points:-

(i) शिखर सम्मेलन में चार प्रमुख पूर्ण सत्र आयोजित किए गए जिनमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणामों पर चर्चा की गई। इन सत्रों में आध्यात्मिक उपचार, पुनर्वास कार्यक्रमों और सामुदायिक संपर्क के माध्यम से समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कि MYAS और MoLE द्वारा संचालित राष्ट्रीय नशामुक्ति प्रयासों के अनुरूप थे।

(ii) शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम काशी घोषणापत्र को औपचारिक रूप से अपनाना था, जो युवाओं में नशे की लत को कम करने के लिए एक पंचवर्षीय रणनीतिक ढाँचा है। इस घोषणापत्र में आध्यात्मिक मार्गदर्शन, राष्ट्रीय संवाद और नागरिक समाज के साथ सहभागिता द्वारा समर्थित समग्र हस्तक्षेप योजनाओं की रूपरेखा दी गई है। इस घोषणापत्र को संयुक्त राष्ट्रीय समिति (JNC) द्वारा सुगम बनाया गया और 250 से अधिक युवा नेताओं ने इसका समर्थन किया।

(iii) विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 के शुभारंभ के लिए एक समर्पित खंड आयोजित किया गया, जो आध्यात्मिक नेतृत्व के प्रयासों पर नज़र रखने, नशा-विरोधी पहलों का मूल्यांकन करने और भविष्य की नीति-निर्माण को दिशा देने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मंच है। शिखर सम्मेलन की घोषणा और परिणामों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई 2026 में इस नेतृत्व संवाद के दौरान की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गति बनी रहे और प्रगति मापी जाए।

4. तमिलनाडु अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा।

तमिलनाडु सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व (ATR) में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु ₹1 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। वन मंत्री के. पोनमुडी द्वारा घोषित इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य विज्ञान-संचालित आवास पुनर्स्थापन, सामुदायिक सहभागिता और संस्थागत भागीदारी के माध्यम से चार देशी हॉर्नबिल प्रजातियों का संरक्षण करना है।

• उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का निर्णय, जिसे वित्त विभाग द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया है और मार्च 2025 में राज्य विधानसभा में घोषित किया गया है, ग्रेट, मालाबार ग्रे, मालाबार पाइड और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पर केंद्रित है। ये पक्षी "वन इंजीनियर" तमिलनाडु के पारिस्थितिक तंत्र में बीज प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• कोयंबटूर जिले में ATR की तलहटी में स्थित इस केंद्र में प्रयोगशालाएँ, सेमिनार हॉल, आवास, नर्सरी इकाइयाँ और क्षेत्रीय सुविधाएँ शामिल होंगी। ये अनुसंधान, निगरानी, प्रजनन, संचलन पारिस्थितिकी, जलवायु प्रभाव अध्ययन और आनुवंशिक विविधता आकलन में सहायता प्रदान करेंगे।

• आवास प्रबंधन उपायों में प्राकृतिक घोंसले बनाने वाले पेड़ों (निजी भूमि पर भी) की सुरक्षा, डिप्टेरोकार्पस इंडिकस, क्रिप्टोकार्या एनामलायन और मिरिस्टिका मालाबारिका जैसी प्रमुख खाद्य प्रजातियों के पौधे उगाना और कृत्रिम घोंसले के बक्से लगाना शामिल है। नीति के तहत भूमि मालिकों को "हॉर्नबिल संरक्षक" के रूप में मान्यता दी जाएगी।

Key Points:-

(i) प्रधान मुख्य संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी, IFS के नेतृत्व में तमिलनाडु वन विभाग इस पहल का समन्वय करेगा। सहयोगी संस्थाओं में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (NCF), सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्रकृति केंद्र (SACON), उन्नत वन्यजीव संरक्षण संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान शामिल हैं, जो विशेषज्ञों द्वारा समर्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे।

(ii) पहली बार, राज्य-स्तरीय व्यापक हॉर्नबिल जनसंख्या सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से संवेदनशील मालाबार पाइड हॉर्नबिल को लक्षित किया जाएगा। आईयूसीएन द्वारा वर्गीकृत संवेदनशील ग्रेट और मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, साथ ही भारतीय ग्रे हॉर्नबिल (सबसे कम चिंताजनक), लक्षित संरक्षण से लाभान्वित होंगे।

(iii) यह केंद्र पश्चिमी घाट, जो एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल है, में जैव विविधता के प्रति तमिलनाडु की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह पहल राज्य भर में शेर-पूंछ वाले मकाक, चिकने-कोट वाले ऊदबिलाव, मद्रास हेजहॉग और बंगाल लोमड़ी के संरक्षण उपायों सहित व्यापक संरक्षण प्रयासों का भी हिस्सा है।

5. भारत ने वैश्विक ऑटोमोटिव लीडर बनने के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 लॉन्च किया।

वैश्विक ऑटो उद्योग में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए, भारत सरकार ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 (AMP 2047) का विकास शुरू किया है। भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) के नेतृत्व में, इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को एक शीर्ष वैश्विक ऑटोमोटिव केंद्र बनाना है।

• AMP 2047 योजना की आधिकारिक शुरुआत जुलाई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित AMP उप-समितियों की उद्घाटन बैठक के दौरान की गई थी।

• इस सत्र की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा मार्गदर्शन में की गई। यह रणनीति नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता

और स्थिरता को बढ़ावा देने के 'विकसित भारत @2047' दृष्टिकोण के अनुरूप है।

• ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047, पूर्ववर्ती ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026 (AMP 2026) की सफलता पर आधारित है और वर्ष 2030, 2037 और 2047 के लिए नए चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित करता है। इन लक्ष्यों का उद्देश्य भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास, निर्यात विस्तार, प्रौद्योगिकी विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

Key Points:-

(i) AMP 2047 की योजना उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करके और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण में निवेश करके वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की है। यह नीतिगत ढाँचा, वैश्विक स्तर पर भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करते हुए, इलेक्ट्रिक और टिकाऊ गतिशीलता की ओर संक्रमण को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा।

(ii) रोडमैप का लक्ष्य ऑटोमोटिव क्षेत्र को भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 12% से अधिक का योगदान देना और ऑटोमोटिव पारिस्थितिकी तंत्र में अनुमानित 65 मिलियन नए रोजगार सृजित करना है। इन लक्ष्यों में मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया के साथ मज़बूत एकीकरण और आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्यात-आधारित विकास शामिल हैं।

(iii) कार्यान्वयन को गति देने के लिए, सरकारी थिंक टैंक, शिक्षाविदों और उद्योग निकायों के विशेषज्ञों वाली सात विशिष्ट उप-समितियाँ गठित की गई हैं। ये उप-समूह ऑटोमोटिव व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मकता में भारत की वैश्विक स्थिति को मज़बूत करने के लिए वर्ष 2030, 2037 और 2047 के लिए लक्षित रणनीतियाँ विकसित करेंगे।

6. दिल्ली विधानसभा हुई डिजिटल, NeVA पहल ने कागज़ रहित कानून निर्माण के युग की शुरुआत की।

दिल्ली विधान सभा ने 'एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन' दृष्टिकोण से जुड़े त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के तहत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को अपनाया, जिससे मानसून सत्र 2025 से पहले वास्तविक समय दस्तावेज़ पहुंच और बढ़ी हुई पारदर्शिता के साथ पूरी तरह से कागज रहित विधायी ढांचे की शुरुआत हुई।

• मार्च 2025 में, दिल्ली विधानसभा - जो कि NeVA में शामिल होने वाली भारत की 28वीं विधायिका बन जाएगी - ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे डिजिटल परिवर्तन की दिशा तय हुई।

• इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक विशेष कार्यान्वयन समिति का गठन किया, जिसमें संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी शामिल थे। गुप्ता ने 100 दिनों के भीतर नेवा को पूरी तरह से चालू करने का आदेश दिया, और जुलाई के मानसून सत्र से पहले इसे लागू करने का लक्ष्य रखा ताकि दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से कागज-रहित हो सके।

• NeVA, भारत के राष्ट्रीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेघराज 2.0 पर आधारित है, जो स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप के माध्यम से डिवाइस-एग्नोस्टिक एक्सेस प्रदान करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म बहुभाषी इंटरफेस, एजेंडा, नोटिस, बिल, समिति रिपोर्ट और अभिलेखागार तक रीयल-टाइम पहुँच प्रदान करता है, जिससे विधायकों और सचिवालय कर्मचारियों के बीच सहज समन्वय को बढ़ावा मिलता है।

Key Points:-

(i) 9 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ, जिसमें से 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रारंभिक किस्त के रूप में वितरित की गई थी, विधानसभा 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्रणाली भी स्थापित कर रही है - जिसका उद्देश्य विधानसभा को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलाना और कागज की खपत और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।

(ii) NeVA के डिजिटल रिपॉजिटरी में सुरक्षित एन्क्रिप्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित खोज की सुविधा है, जिससे विधायक सेकंडों में ही राज्यों की पिछली बहसों, मंत्रियों के जवाबों और तुलनात्मक शोध को प्राप्त कर सकते हैं। इससे विधायी दक्षता, डेटा अखंडता और नागरिकों के प्रति जवाबदेही बढ़ती है।

(iii) यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "एक राष्ट्र, एक अनुप्रयोग" नीति के अनुरूप है, जो पारदर्शी और टिकाऊ शासन की ओर बदलाव का संकेत देती है। दिल्ली का लक्ष्य एक आदर्श उदाहरण बनना है, जहाँ बुनियादी ढाँचे में सुधार के साथ-साथ एक आधुनिक ई-लाइब्रेरी, विधायी संग्रहालयों के भ्रमण और अपने विरासत विधानसभा भवन में इंटरैक्टिव प्रदर्शनियाँ भी शामिल हैं।

7. LIC ने बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) न गोवा में आयोजित राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन सम्मेलन ('अनुभूति') (8-10 जुलाई 2025) के दौरान भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य महिला एजेंटों को सशक्त बनाकर और घरेलू आय को बढ़ाकर ग्रामीण भारत में LIC की बीमा सखी योजना का विस्तार करना है।

• LIC ने 21 जुलाई 2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे बीमाकर्ता की ग्रामीण पहुँच रणनीति दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अनुरूप हो गई। इस समझौते को 'अनुभूति' सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें वंचित क्षेत्रों में बीमा जागरूकता और वितरण नेटवर्क के विस्तार हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर बल दिया गया।

• दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना विशेष रूप से 18-70 वर्ष की आयु की ग्रामीण महिलाओं के लिए बनाई गई है, जिन्होंने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है। यह उन्हें LIC बीमा एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाती है, उन्हें

व्यापक प्रशिक्षण, करियर पथ और प्रदर्शन-आधारित वजीफे और कमीशन के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है।

• इस योजना के तहत, LIC की महिला एजेंटों—जिन्हें 'बीमा सखी' कहा जाता है—को मासिक वजीफा मिलता है: पहले वर्ष ₹7,000, दूसरे वर्ष ₹6,000 और तीसरे वर्ष ₹5,000, साथ ही कमीशन आय भी। LIC का लक्ष्य तीन वर्षों के भीतर 2 लाख महिलाओं की भर्ती करना है, और योजना शुरू होने के बाद पहले महीने में ही 50,000 से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं।

Key Points:-

(i) यह समझौता ज्ञापन DAY-NRLM के ग्रामीण आजीविका नेटवर्क और LIC के बीमा वितरण के बीच तालमेल को सक्षम बनाता है, जिससे बीमा सखियाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत तक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेंगी। इस पहल से गाँवों में बीमा जागरूकता बढ़ने और घरेलू आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर महिला प्रधान परिवारों के लिए।

(ii) LIC के प्रबंध निदेशक और CEO सिद्धार्थ मोहंती ने बताया कि कंपनी ने पहले वर्ष के दौरान वजीफा और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 840 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका लक्ष्य बीमा सखियों द्वारा पॉलिसी बिक्री में वृद्धि के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम सृजन करना है।

(iii) लचीले कार्य समय और डिजिटल उपकरणों के साथ, बीमा सखी कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाली एक स्थायी बीमा टीम का निर्माण करना है। इस योजना के स्नातक एलआईसी विकास अधिकारी के पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक आजीविका को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण बाजारों में LIC की उपस्थिति मजबूत होगी।

INTERNATIONAL

1. रोम में 88वीं Codex कार्यकारी समिति की बैठक में भारत के बाजरा मानकों को वैश्विक प्रशंसा मिली।

14-18 जुलाई 2025 तक रोम, इटली में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) मुख्यालय में आयोजित Codex एलीमेंटेरियस आयोग (CCEXEC88) की 88वीं कार्यकारी समिति की बैठक में, साबुत बाजरा अनाज के लिए वैश्विक मानकों को तैयार करने में भारत के नेतृत्व को औपचारिक मान्यता मिली, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा शासन में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

• भारत ने माली, नाइजीरिया और सेनेगल के साथ मिलकर साबुत बाजरा के लिए एक समूह मानक के विकास का नेतृत्व किया, जो सह-अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। 2024 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (CAC47) के 47वें सत्र के दौरान मूल रूप से स्वीकृत इस पहल की CCEXEC88 में सदस्य देशों द्वारा गहन सराहना की गई।

• बैठक के दौरान, अप्रैल 2025 में आयोजित अनाज, दलहन और फलियों (CCCPL11) पर Codex समिति के 11वें सत्र में चर्चा के बाद बाजरा मानकों के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया, जिससे भारत के रणनीतिक इनपुट को बल मिला।

• CCEXEC88 का उद्घाटन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया, जिनमें एफएओ के उप महानिदेशक और कैबिनेट निदेशक गॉडफ्रे मैग्वेन्ज़ी, विश्व

स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण के सहायक महानिदेशक डॉ. जेरेमी फरार, कोडेक्स आयोग के अध्यक्ष डॉ. एलन अज़ेगेले के साथ शामिल थे, जिन्होंने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को रेखांकित किया।

Key Points:-

(i) बाजरा मानकों के अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के भारत के प्रतिनिधिमंडल ने सीसीईएक्सईसी88 में ताजा खजूर के लिए नए मापदंडों का समर्थन भी देखा, जिन्हें नवंबर 2025 में सीएसी48 में पूर्ण रूप से अपनाने की योजना है, और ताजा हल्दी और ब्रोकोली के लिए आगामी मानकों में भारत के नेतृत्व को हरी झंडी दिखाई।

(ii) भारत ने Codex रणनीतिक योजना 2026-2031 को आकार देने में भी निर्णायक भूमिका निभाई और स्मार्ट (विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध) प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) की वकालत की। इसने भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और तिमोर-लेस्ते में क्षमता निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई और एफएओ से प्रशंसा अर्जित की।

(iii) CCEXEC88 की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि भारत ने कम सक्रिय सदस्य देशों द्वारा कोडेक्स ट्रस्ट फंड (CTF) के उपयोग को बढ़ाने पर ज़ोर दिया, जिससे भारत की सलाहकार भूमिका उजागर हुई। भारत 2014 से मसालों और पाककला जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) की अध्यक्षता भी कर रहा है।

2. ADB ने त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 975 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी।

मनीला, फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक (ADB) ने त्रिपुरा राज्य के नौ औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जुलाई 2025 तक ₹975.26 करोड़ (लगभग 85.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के ऋण को मंज़ूरी दी है। यह प्रमुख वित्तीय सहायता त्रिपुरा के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में टिकाऊ औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए है।

- **यह ऋण त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम (TIDC) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसने निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक शेड, बिजली और विद्युत अवसंरचना, अग्निशमन केंद्र और 34 पहुँच मार्ग बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इस पहल का उद्देश्य नए उद्यमियों को आकर्षित करना और राष्ट्रीय विनिर्माण उत्पादन में त्रिपुरा की हिस्सेदारी बढ़ाना भी है।**

- **यह परियोजना बोधजंगनगर, आरके नगर, डुकली, एएन नगर, कुमारघाट, धजानगर, धर्मनगर, दीवानपासा और सरसीमा में नौ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करेगी।**

- **इसमें दो नए आवंटित स्थल शामिल हैं - शांतिबाजार (दक्षिण त्रिपुरा में 127 एकड़) और फटीक्रोय (उनाकोटी में 28 एकड़) - जिन्हें हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए सौंपा गया है।**

Key Points:-

(i) TIDC ने नए उद्योगों को आवंटन के लिए 24 निष्क्रिय इकाइयों से 28 एकड़ भूमि वापस ले ली है, तथा सीमांकन का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

(ii) वर्तमान में, त्रिपुरा में केवल दो पूर्णतः चालू विनिर्माण क्षेत्र हैं, लेकिन सात और प्रस्तावित हैं। राज्य में 1,10,000 हेक्टेयर रबर के बागान हैं और प्लाईवुड से संबंधित उद्योगों के लिए 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान पहले ही कर ली गई है, जिससे क्षेत्र की मूल्यवर्धित विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी।

(iii) ADB द्वारा वित्तपोषित परियोजना से त्रिपुरा को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने और पूर्वोत्तर में महत्वपूर्ण रोजगार और निवेश के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

3. गीता गोपीनाथ ने हार्वर्ड लौटने के लिए IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रथम उप-प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटने की प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए अगस्त 2025 के अंत तक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस कदम से IMF में उनके छह से अधिक वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिसमें वैश्विक समष्टि अर्थशास्त्र में नेतृत्वकारी भूमिकाओं में लगभग चार वर्ष शामिल हैं।

• जनवरी 2022 में नियुक्त, गोपीनाथ, जेफ्री ओकामोटो के बाद, आईएमएफ की पहली महिला प्रथम उप-प्रबंध निदेशक बनीं। इससे पहले, उन्होंने जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक फंड की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया था, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने विशिष्ट शैक्षणिक करियर के बाद IMF में शामिल हुई थीं।

• गोपीनाथ ने 2019 में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में IMF में प्रवेश किया था। उन्होंने कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध सहित कई गंभीर वैश्विक संकटों के दौरान यह भूमिका निभाई थी। उन्होंने 21 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर अपना वर्तमान उप-कार्यभार ग्रहण किया और प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के सीधे अधीन कार्य किया।

• अपने कार्यकाल के दौरान, गोपीनाथ ने "महामारी पत्र" जैसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक और नीतिगत प्रयासों का नेतृत्व किया, बहुपक्षीय वित्तीय निगरानी का समन्वय किया, और राजकोषीय नीति, मौद्रिक ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय ऋण और वैश्विक व्यापार पर आईएमएफ रणनीतियों को आकार दिया।

Key Points:-

(i) IMF ने पुष्टि की है कि वह अगस्त 2025 के अंत में पद छोड़ देंगी, जिससे संस्था के साथ उनके छह साल से ज़्यादा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उनके जाने से एक उत्तराधिकारी का रास्ता साफ हो गया है—पारंपरिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नामित, क्योंकि आईएमएफ में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उसी के पास है—और यह पद फंड के जलवायु और लैंगिक एजेंडे पर नए सिरे से अमेरिकी जाँच के दौर में आने की उम्मीद है।

(ii) अपने वक्तव्य में, गीता गोपीनाथ ने अपनी शैक्षणिक जड़ों की ओर लौटने के बारे में उत्साह व्यक्त किया, और कहा कि वह हार्वर्ड में "वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त

और समष्टि अर्थशास्त्र में अनुसंधान की सीमा को आगे बढ़ाने और अर्थशास्त्रियों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने" के लिए तत्पर हैं।

(iii) उनके जाने से वैश्विक वित्तीय समुदाय का व्यापक ध्यान आकर्षित हुआ। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने गोपीनाथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक "असाधारण बौद्धिक नेता" बताया, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा प्रस्तावित लोम्पटिशन संगठन के मूल मिशन को लेकर चल रही बहस का संकेत देता है।

BANKING & FINANCE

1. SBI ने रिकॉर्ड तोड़ पूंजी निवेश के तहत QIP के जरिए 25,000 करोड़ रुपये जुटाए।

भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में ₹817 प्रति शेयर की दर से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के ज़रिए 30.59 करोड़ शेयर जारी करके ₹25,000 करोड़ जुटाए हैं। 16 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा QIP है, जो मज़बूत संस्थागत विश्वास को दर्शाता है और SBI के पूंजी आधार को मज़बूत करने के उद्देश्य से है।

• 16 जुलाई 2025 को शुरू किया गया यह QIP, SBI द्वारा आठ वर्षों में पहली बार इक्विटी पूंजी जुटाने का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसके कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) बफर को मज़बूत करने और भविष्य में ऋण विस्तार को समर्थन देने की एक बड़ी पहल है। निवेशकों की गहरी भागीदारी को आकर्षित करने के लिए, इस इश्यू का मूल्य बाजार मूल्य से थोड़ा कम ₹817 रखा गया था।

• SBI ने विदेशी दीर्घकालिक फंड, LIC, म्यूचुअल फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड सहित संस्थागत निवेशकों को 30.59 करोड़ नए शेयरों की पेशकश की। इस व्यापक भागीदारी के परिणामस्वरूप ओवरसब्सक्रिप्शन हुआ, और कुल बोलियाँ ₹1.10 लाख करोड़ तक पहुँच गईं, जो निर्धारित मूल्य से 4.5 गुना अधिक है।

• जुटाई गई पूँजी ने SBI के CET-1 अनुपात को 10.81% से बढ़ाकर लगभग 11.5% कर दिया, हालाँकि यह अभी भी निजी क्षेत्र के औसत ~14% से पीछे है। इससे SBI को बेसल III नियमों के तहत भविष्य की आवश्यकताओं की तैयारी करते हुए, ₹8 ट्रिलियन (लगभग 93 अरब डॉलर) की ऋण वृद्धि की योजना को आगे बढ़ाने की स्थिति में लाया गया है।

Key Points:-

(i) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एक प्रमुख एंकर निवेशक के रूप में उभरा, जिसने ₹50,000 करोड़ मूल्य के शेयर खरीदे—जिससे उसकी हिस्सेदारी 9.21% से बढ़कर 9.49% हो गई। अन्य प्रतिभागियों में ब्लैकरॉक, मार्शल वेस, HDFC म्यूचुअल और क्वांट एमएफ शामिल थे, जिन्हें घरेलू और वैश्विक दोनों संस्थानों से मज़बूत समर्थन मिला।

(ii) SBI ने QIP के प्रबंधन के लिए छह प्रमुख निवेश बैंकों को चुना: सिटीग्रुप, HSBC, मॉर्गन स्टेनली, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ICICI सिक्योरिटीज और SBI कैपिटल मार्केट्स। कानूनी सलाहकारों में सिरिल अमरचंद मंगलदास, लिंकलेटर, शियरमैन एंड स्टर्लिंग और एलन एंड ओवरी शामिल थे।

(iii) QIP के साथ-साथ, SBI के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 में ₹20,000 करोड़ के बॉन्ड जारी करने (बेसल III-अनुपालक टियर 1 और टियर 2) को

मंज़ूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य कुल ₹45,000 करोड़ की पूंजी निवेश करना है। अनुमान बताते हैं कि QIP SBI के इक्विटी पर रिटर्न (RoE) को लगभग 17% से घटाकर लगभग 16% कर देगा, जिससे पूंजी की मज़बूती को टिकाऊ विकास रणनीति के साथ जोड़ा जा सकेगा।

2. विश्व बैंक की वैश्विक फाइंडेक्स रिपोर्ट 2025: भारत में 2024 में 89% वित्तीय खाता स्वामित्व दर्ज होगा, लेकिन 16% निष्क्रियता का सामना करना पड़ेगा।

जुलाई 2025 में, विश्व बैंक (WB) ने "डिजिटल अर्थव्यवस्था में कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन" शीर्षक से अपनी ग्लोबल फ़ाइंडेक्स डेटाबेस रिपोर्ट का पाँचवाँ संस्करण जारी किया। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में वित्तीय खातों का स्वामित्व 2024 तक 89% तक पहुँच जाएगा, जो 2011 से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। हालाँकि, देश में निष्क्रियता की दर भी ऊँची है, जहाँ पिछले 12 महीनों में 16% खाताधारक अपने खातों का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

• ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्तीय खाता स्वामित्व 2021 में 77.5% से बढ़कर 2024 में 89% हो गया। यह 2011 में केवल 35% से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जो सरकार के नेतृत्व वाली डिजिटल और वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे जन धन योजना और आधार-सक्षम भुगतान की सफलता को दर्शाता है।

• उच्च स्वामित्व दर के बावजूद, रिपोर्ट बताती है कि 2021 में 35% भारतीय बैंक खाते निष्क्रिय थे, और 2024 में भी, 16% खाते निष्क्रिय रहे—जो वैश्विक औसत 6% से कहीं ज़्यादा है। निष्क्रियता को पिछले 12 महीनों में खातों का उपयोग न करने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पहुँच और उपयोग के बीच अंतर को दर्शाता है।

• भारत में 89% वित्तीय खाताधारकों में से 88.7% के पास बैंक/वित्तीय संस्थान खाता या मोबाइल मनी खाता होने की सूचना है। हालाँकि, पिछले वर्ष केवल 48.5% भारतीय वयस्कों ने ही अपने खातों का उपयोग डिजिटल लेनदेन के लिए किया। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के खाता स्वामित्व में लगातार वृद्धि के बावजूद, लैंगिक अंतर अभी भी बना हुआ है, दुनिया भर में 70 करोड़ महिलाएँ अभी भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं।

Key Points:-

(i) वैश्विक वित्तीय खाता स्वामित्व 2024 में 79% था, जो 2011 में 51% से 28 प्रतिशत अंक अधिक है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, स्वामित्व 2011 में 42% से बढ़कर 2024 में 75% हो गया। इस बीच, उच्च आय वाले देशों में, यह 2011 में 87% से बढ़कर 2024 में 95% हो गया, जो मजबूत उपयोग और कम निष्क्रियता के स्तर को दर्शाता है।

(ii) 2024 तक, दुनिया भर में 1.3 अरब वयस्क बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहेंगे, जिनमें से ज़्यादातर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से हैं। विश्व बैंक ने ज़ोर देकर कहा कि सिर्फ़ वित्तीय पहुँच ही अपर्याप्त है, जब तक कि उसे नियमित उपयोग, डिजिटल सशक्तिकरण और वित्तीय साक्षरता के साथ न जोड़ा जाए—एक ऐसा क्षेत्र जहाँ भारत जैसे देशों को अभी भी केंद्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

(iii) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), PMJDY

(प्रधानमंत्री जन धन योजना) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं सहित डिजिटल बैंकिंग में भारत की प्रगति की दुनिया भर में सराहना हुई है। हालाँकि, विश्व बैंक की सिफारिश है कि भारत अब खाता उपयोग दरों में सुधार, वित्तीय शिक्षा के माध्यम से निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने और डिजिटल सेवाओं की पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे।

3. RBI ने RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42(6)(ए) के तहत NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है। इसे RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42(6)(a) के अंतर्गत अनुसूची II में शामिल किया गया है, जिससे बैंक को RBI की तरलता और पुनर्वित्त सुविधाओं तक सीधी पहुँच प्राप्त होगी।

• इस मान्यता के परिणामस्वरूप, NSDL पेमेंट्स बैंक अब एक अनुसूचित बैंक (SB) के रूप में वर्गीकृत है, जिससे उसे सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत धन उधार लेने और तरलता समायोजन सुविधा (LAF) परिचालनों में भाग लेने की अनुमति मिलती है। ये विशेषाधिकार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर बैंक की तरलता पहुँच और जोखिम प्रबंधन को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाएंगे।

• इस उन्नयन के साथ, NSDL पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक के बाद, अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पाँचवाँ पेमेंट्स बैंक बन गया है। यह समावेशन वित्तीय अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और विनियमित मानदंडों के तहत व्यापक मौद्रिक पहुँच को सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

• SB का दर्जा पाने के लिए, बैंक को RBI की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। बुनियादी एसबी मान्यता के लिए न्यूनतम ₹5 लाख की चुकता पूंजी आवश्यक है, लेकिन एक वाणिज्यिक अनुसूचित बैंक के रूप में कार्य करने के लिए, RBI ₹100 करोड़ की पूंजी की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बनाए रखना होगा और बैंक दर ऋण, क्लियरिंगहाउस सदस्यता, और प्रथम श्रेणी विनिमय बिलों के मोचन के लिए पात्र होना होगा।

Key Points:-

(i) संबंधित कदम में, RBI ने जून 2025 में एक प्रमुख शहरी सहकारी बैंक (UCB) विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड (VSBL) को भी अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया।

(ii) इस अनुमोदन के साथ, विश्वेश्वर बैंक भारत का 50वां सहकारी बैंक और RBI की अनुसूची II के तहत सूचीबद्ध होने वाला तीसरा UCB बन गया, जिससे भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में सहकारी क्षेत्र का एकीकरण मजबूत हुआ।

(iii) यह दोहरी मान्यता, RBI के रणनीतिक प्रयास को उजागर करती है, जिसके तहत विशिष्ट और सहकारी

बैंकिंग खंडों को अपने मुख्य मौद्रिक उपकरणों और वित्तीय प्रणालियों तक सीधी पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाया जाएगा।

SPORTS

1. ICC ने दो स्तरीय टेस्ट प्रणाली पर विचार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया और 2026 में चैंपियंस लीग टी20 को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया।

जुलाई 2025 में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने द्वि-स्तरीय टेस्ट क्रिकेट संरचना लागू करने की संभावना पर विचार करने के लिए एक आठ-सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया। ICC के CEO संजोग गुप्ता और जय शाह के नेतृत्व में, इस कदम को सिंगापुर में ICC की वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान औपचारिक रूप दिया गया।

• आठ सदस्यीय कार्य समूह में जय शाह, रिचर्ड गोल्ड (इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड - ECB के प्रमुख) और टॉड ग्रीनबर्ग (क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO) जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं, साथ ही विभिन्न ICC सदस्य बोर्डों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस समिति को 2025 के अंत तक अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

• टेस्ट प्रारूप में संभावित बदलाव विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) को प्रभावित कर सकता है, जिसमें वर्तमान में नौ टीमें शामिल हैं। यदि इसे लागू किया जाता है, तो नया दो-स्तरीय मॉडल इसे दो डिवीजनों में पुनर्गठित करेगा, जिनमें से प्रत्येक में छह टीमें होंगी, ताकि क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और संतुलन को बढ़ावा दिया जा सके।

• वर्तमान प्रारूप में कोई भी परिवर्तन तुरंत लागू नहीं होगा, बल्कि अगले WTC चक्र में, विशेष रूप से 2027 से 2029 तक लागू किया जाएगा। यह समयरेखा क्रिकेट समुदाय द्वारा मूल्यांकन और अनुकूलन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

Key Points:-

(i) द्वि-स्तरीय प्रणाली के अलावा, ICC की वार्षिक आम बैठक (AGM) ने यह भी पुष्टि की कि वर्ष 2027, 2029 और 2031 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। यह 2021, 2023 और 2025 में इंग्लैंड में WTC फाइनल के सफल आयोजन के बाद हुआ है, जिससे प्रमुख क्रिकेट आयोजनों के नियमित मेज़बान के रूप में इंग्लैंड की भूमिका और मज़बूत हुई है।

(ii) ICC ने वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान चर्चा के साथ, फ्रैंचाइज़ी-आधारित अंतर्राष्ट्रीय T20 प्रतियोगिता, चैंपियंस लीग T20 (CLT20) को फिर से शुरू करने की भी घोषणा की। यह टूर्नामेंट, जो पिछली बार 2014 में आयोजित हुआ था, सितंबर 2026 में वापसी की संभावना है। पिछले संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने बेंगलुरु में आयोजित फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को हराया था।

(iii) इसके अतिरिक्त, ICC ने ICC मुख्य कार्यकारी समिति (CEC) के लिए तीन नए एसोसिएट सदस्य प्रतिनिधियों को शामिल किया: गुरुमूर्ति पलानी (फ्रांस क्रिकेट), अनुराग भट्टनागर (क्रिकेट हांगकांग), और

गुरदीप क्लेयर (क्रिकेट कनाडा)। क्रिकेट की वैश्विक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में, तिमोर-लेस्ते और ज़ाम्बिया को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया गया, जिससे ICC सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 108 हो गई।

2. भारत 23 वर्षों के बाद 2025 में FIDE विश्व कप की मेजबानी करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) ने आधिकारिक तौर पर भारत को 2025 FIDE विश्व कप की मेज़बानी का अधिकार दे दिया है। यह विश्व कप 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जो 23 वर्षों में पहली बार होगा। इस टूर्नामेंट में 206 खिलाड़ी एक उच्च-दांव वाले एकल-एलिमिनेशन प्रारूप में भाग लेंगे, जिसमें 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए तीन क्वालीफिकेशन स्थान होंगे।

• 2025 संस्करण 23 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित फिडे विश्व कप की भारत में वापसी का प्रतीक है, इससे पहले 2002 में हैदराबाद में इसकी मेजबानी की गई थी, जहां विश्वनाथन आनंद ने खिताब जीता था।

• 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलने वाले इस 29-दिवसीय आयोजन में 206 प्रतियोगी एकल-नॉकआउट ब्रैकेट में भाग लेंगे। शीर्ष 50 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी दूसरे दौर में प्रवेश करेंगे, जबकि शेष प्रतियोगी (51-206) पहले दौर में भाग लेंगे। प्रत्येक दौर तीन दिनों तक चलेगा—दो क्लासिकल गेम्स के बाद रैपिड/ब्लिट्ज़ टाईब्रेक होंगे।

• शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित स्थान अर्जित करेंगे, जो कि मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन को चुनौती देने का अंतिम रास्ता होगा, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक दबाव भी काफी बढ़ जाएगा।

Key Points:-

(i) शतरंज में भारत का कद तेज़ी से बढ़ा है—डी गुकेश 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने, और देश ने हाल ही में 2024 शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक हासिल किए। प्रज्ञानंद (विश्व कप 2023 उपविजेता) और अर्जुन एरिगैसी जैसे भारतीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी घरेलू मैदान पर सफलता के प्रबल दावेदार हैं।

(ii) हालांकि भारत को मेजबान देश के रूप में पुष्टि कर दी गई है, लेकिन सटीक शहर - गोवा, अहमदाबाद, नई दिल्ली या मुंबई - अभी भी विचाराधीन है, जिसे FIDE और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई 2025 को मनाया गया।

विश्व मस्तिष्क दिवस 2025, 22 जुलाई को "सभी आयु वर्गों के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य" वैश्विक थीम के साथ मनाया गया। विश्व न्यूरोलॉजी महासंघ (WFN) द्वारा शुरू किया गया यह दिवस मस्तिष्क स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और जीवन के सभी चरणों में तंत्रिका संबंधी देखभाल पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह अभियान UN-IGAP (अंतर-क्षेत्रीय वैश्विक कार्य योजना) और विश्व स्वास्थ्य संगठन की तंत्रिका संबंधी रणनीति के अनुरूप है।

- **विश्व न्यूरोलॉजी फेडरेशन (WFN) ने 22 जुलाई 1957 को अपनी स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2014 में विश्व मस्तिष्क दिवस मनाना शुरू किया। यह विचार 2013 में प्रस्तावित किया गया था और फरवरी 2014 में WFN बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था।**

- **पहले विश्व मस्तिष्क दिवस का विषय था "हमारा मस्तिष्क, हमारा भविष्य।" तब से, प्रत्येक वर्ष किसी भिन्न तंत्रिका संबंधी विकार या मस्तिष्क स्वास्थ्य पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।**

- **2025 में, "सभी उम्र के लोगों के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य" थीम एक जीवन-पद्धति दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है—जन्मपूर्व मस्तिष्क विकास से लेकर वृद्धों की देखभाल तक—जागरूकता, रोकथाम, शिक्षा, पहुँच और वकालत पर ज़ोर देते हुए। इस अभियान का उद्देश्य स्ट्रोक, मनोभ्रंश, मिर्गी, माइग्रेन और पार्किंसंस जैसी प्रमुख तंत्रिका संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, जो वैश्विक रोग भार में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।**

Key Points:-

(i) इस वर्ष का यह आयोजन वैश्विक तंत्रिका संबंधी मृत्यु दर और विकलांगता को कम करने के व्यापक मिशन का हिस्सा है। तंत्रिका संबंधी विकारों के कारण प्रति वर्ष 90 लाख से अधिक मौतें होती हैं, इसलिए यह अभियान बहु-क्षेत्रीय सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, जहाँ तंत्रिका संबंधी देखभाल की पहुँच सीमित है।

(ii) WFN ने सरकारों, स्कूलों, चिकित्सा पेशेवरों और नागरिक समाज से कलंक को खत्म करने, प्रारंभिक पहचान में सुधार करने और न्यायसंगत न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का निर्माण करने के लिए स्क्रीनिंग ड्राइव, शैक्षिक कार्यक्रम, वेबिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया है।

(iii) 2025 अभियान सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में काम करते हुए UN-IGAP (2022-2031) के कार्यान्वयन का भी समर्थन करता है।

2. राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई 2025 को मनाया गया।

राष्ट्रीय ध्वज दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, जो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा तिरंगे को औपचारिक रूप से अपनाने की याद में मनाया जाता है—आज़ादी से कुछ हफ़्ते पहले। इस वर्ष, समारोहों में राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और बहु-पीढ़ी के गौरव के लिए ध्वज के स्थायी महत्व का सम्मान किया गया।

• भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा ("तिरंगा") के नाम से जाना जाता है, में तीन क्षैतिज पट्टियाँ—केसरिया, सफ़ेद और हरा—और 24 तीलियों वाला एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है। इसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जो साहस, शांति, उर्वरता और धार्मिकता का प्रतीक है।

• पहला अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज—जिसे 1906 में कलकत्ता में प्रदर्शित किया गया—कई दशकों की मेहनत के बाद विकसित हुआ। 14 जुलाई 1947 को, एक ध्वज समिति ने चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को अपनाया। इसे औपचारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्वीकृत और प्रस्तुत किया गया।

Key Points:-

(i) इस समारोह में ध्वजारोहण समारोह, शैक्षिक कार्यक्रम, पोस्टर और नारा प्रतियोगिताएँ, और भारतीय ध्वज संहिता पर चर्चाएँ शामिल हैं। देश भर के स्कूल, संस्थान और गैर-सरकारी संगठन इस दिन "एक राष्ट्र, एक ध्वज" की थीम के साथ ध्वज सम्मान और शिष्टाचार पर ज़ोर देते हैं।

(ii) राष्ट्रीय ध्वज दिवस स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, राष्ट्रीय एकता और नागरिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है। यह भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और सांस्कृतिक आख्यान में ध्वज के स्थान को सुदृढ़ करता है और नागरिकों—विशेषकर युवाओं—को इसकी गरिमा और मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।

DEFENCE

1. GRSE ने अंतिम पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत 'INS अजय' लॉन्च किया और भारतीय नौसेना के लिए 6,311 करोड़ रुपये की ASW-SWC परियोजना पूरी की।

भारत के तटीय और पानी के नीचे के समुद्री रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, रक्षा मंत्रालय (MoD) के तहत एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में GRSE के शिपयार्ड में अर्नाला-क्लास एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) श्रृंखला में 8वें और अंतिम जहाज 'INS अजय' को लॉन्च किया।

• INS अजय का औपचारिक उद्घाटन वाइस एडमिरल किरण देशमुख की पत्नी प्रिया देशमुख ने किया, जो वर्तमान में भारतीय नौसेना के मैटेरियल प्रमुख (COM) के रूप में कार्यरत हैं। यह उद्घाटन रक्षा मंत्रालय के साथ अप्रैल 2019 में हुए एक ऐतिहासिक अनुबंध के तहत जीआरएसई द्वारा निर्मित आठ ASW-SWC जहाजों के निर्माण चरण के पूरा होने का प्रतीक है, जिसका मूल्य ₹6,311 करोड़ है।

• पुराने अभय-श्रेणी के युद्धपोतों को आधुनिक उथले पानी में पनडुब्बी रोधी गश्ती जहाजों से बदलने के लिए ASW-SWC परियोजना को मंजूरी दी गई। ये जहाज विशेष रूप से तटीय जल में संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और पानी के भीतर बेहतर पहचान और संचालन के लिए उच्च-स्तरीय सोनार प्रणालियों, हल्के टॉरपीडो, ASW रॉकेट लॉन्चरों और क्लोज-इन वेपन सिस्टम (CIWS) से लैस हैं।

• INS अजय, जिसका नाम पेनेंट नंबर P34 और यार्ड नंबर 3034 है, एक 77.6 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा स्टील्थ-सक्षम युद्धपोत है, जो पूर्ण-स्पेक्ट्रम अंडरवाटर निगरानी, पनडुब्बी-रोधी अभियानों और तटीय गश्ती कार्यों के लिए अनुकूलित है। यह भारत की उथले पानी में युद्ध की तैयारी और तटीय सुरक्षा ग्रिड को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है।

Key Points:-

(i) श्रृंखला का प्रमुख जहाज, INS अर्नाला (P68), 8 मई 2025 को वितरित किया गया और 18 जून 2025 को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। MoD-GRSE सौदे के तहत सभी 8 जहाजों की डिलीवरी 2026 तक निर्धारित है।

(ii) 8 अर्नाला श्रेणी के ASW-SWC जहाजों की पूरी श्रेणी में शामिल हैं: INS अर्नाला, INS अंजादीप, INS एंड्रोथ, INS अमिनिदिवी, INS अग्रे, INS अक्षय, INS माहे और INS अजय - सभी का नाम भारतीय क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपों के नाम पर रखा गया है।

(iii) यह परियोजना रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत के प्रयासों को मजबूत करती है और दक्षिण एशिया में एक अग्रणी युद्धपोत निर्माता के रूप में GRSE की भूमिका को रेखांकित करती है, जिसने भारतीय और विदेशी नौसेनाओं को 100 से अधिक जहाज वितरित किए हैं।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. ISRO का GSLV-F16 संयुक्त ISRO-NASA पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह NISAR का प्रक्षेपण करेगा।

ISRO का जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV)-F16, NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह को लेकर 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित होगा। ₹1.5 अरब का यह ऐतिहासिक मिशन वैश्विक पृथ्वी-निगरानी के लिए भारत-अमेरिका सहयोग में एक बड़ी छलांग है।

• ISRO और NASA द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, NISAR, **12 मीटर तैनात करने योग्य एल-बैंड और एस-बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) को मिलाकर हर 12 दिनों में 5-10 मीटर रिज़ॉल्यूशन पर वैश्विक भूमि और बर्फ की सतहों का मानचित्रण करता है। यह मिशन 2,392 किलोग्राम का भारी पेलोड ले जाता है, जिससे यह 1.5 बिलियन डॉलर की लागत के साथ अब तक का सबसे महंगा पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह बन जाता है।**

• इस मिशन में GSLV-F16 (Mk II) का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक 3-चरणीय रॉकेट है जिसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप-ऑन और विकास इंजन द्वारा संचालित एक दूसरा चरण (GS2) है। यह रॉकेट 2,500 किलोग्राम भार को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा

(GEO) और 5,000 किलोग्राम भार को निम्न पृथ्वी कक्षा (LOW Earth Orbit) तक ले जा सकता है, जो इसे इस मिशन के लिए आदर्श बनाता है।

• ISRO ने 24 अप्रैल 2025 को IPRC महेंद्रगिरि से श्रीहरिकोटा के लिए GSLV के GS2 द्रव चरण को हरी झंडी दिखाई और प्रक्षेपण अभियान अप्रैल 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ। प्रक्षेपण के करीब आने पर GSLV-F16 और निसार के लिए अंतिम प्रक्षेपण-पूर्व जांच चल रही है।

Key Points:-

(i) NISAR सभी मौसम और प्रकाश की स्थितियों के तहत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, बर्फ की चादर की गतिशीलता, समुद्र-स्तर में वृद्धि, भूजल स्तर, भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी करेगा, जिससे जलवायु विज्ञान, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचा नीति में सहायता मिलेगी।

(ii) ISRO ₹788 करोड़ (~95 मिलियन डॉलर) का योगदान देता है, जबकि नासा प्रमुख रडार सिस्टम और डेटा आर्किटेक्चर प्रदान करता है, जो अंतरिक्ष में एक रणनीतिक भारत-अमेरिका साझेदारी को दर्शाता है। NISAR उन्नत प्रक्षेपण यान क्षमताओं के माध्यम से "आत्मनिर्भर भारत रक्षा" को सुदृढ़ करता है।

(iii) प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को 17:40 IST पर निर्धारित है, जो NISAR को लगभग 743 किमी की सूर्य-समकालिक कक्षा में स्थापित करेगा, और मिशन की अवधि कम से कम तीन वर्ष होगी। यह डेटा दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा, जो खुले विज्ञान और वैश्विक पर्यावरण निगरानी को बढ़ावा देगा।

Static GK

Codex Alimentarius Commission (CAC)	अध्यक्ष : डॉ. एलन अज़ेगेले	मुख्यालय : रोम, इटली
State Bank of India	अध्यक्ष: चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	मुख्यालय: मुंबई
Asian Development Bank	राष्ट्रपति : मसातो कांडा	मुख्यालय : मनीला, फ़िलीपींस
Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) : पीआर हरि	मुख्यालय : कोलकाता, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल)
ISRO	अध्यक्ष: डॉ. वी. नारायणन	मुख्यालय: बेंगलुरु
Assam	मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा	राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
International Cricket Council (ICC)	अध्यक्ष : जय शाह	मुख्यालय : दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
Uttar Pradesh	मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ	राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
Tamil Nadu	मुख्यमंत्री: एम के स्टालिन	राज्यपाल: आर. एन. रवि
International Monetary Fund (IMF)	प्रबंध निदेशक: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा	मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., (USA)
World Bank (WB)	CFO : अंशुला कांत	मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
LIC	स्थापना: 1956	मुख्यालय: मुंबई